7 सितम्बर 2010 की हड़ताल को शानदार रूप से सफल बनाओ

मांगें

1. अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि पर रोक लगाओ।
2. पीएसयूज के शेयरों का विनिवेश बंद करो।
3. बीएसएनएल पर साम पित्रोदा कमेटी की सभी प्रतिगामी सिफारिशों को रद्द करो।
4. बीएसएनएल की वित्तीय जीवंतता सुनिश्चित करो।
5. रोजगार की रक्षा करो।
6. श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करो।
7. सभी असंगठित क्षेत्र मजदूरों को, गरीबी रेखा से ऊपर के मजदूरों समेत, असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के तहत लाओ।

साथियों,

पूंजीवादी प्रणाली अब अपने संकट से निपटने के लिए उत्पादन की बजाए लूट पर और इसके जरिए शीघ्र लाभ कमाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि की जाती है, रोजगारों में कटौती की जाती है, पीएसयूज को कौड़ियों के मोल बेचा जाता है, पेन्शन पर हमला किया जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा को बड़े कारोबार में बदल दिया जाता है, खादानों को मामूली दरों पर हस्तांतरित किया जाता है, सार्वजनिक धन को करों में छूट देने के नाम पर बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जाता है, श्रम कानूनों का उल्लंघन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार उच्च शिखरों पर पहुंच गया है, देश की 77 % आबादी अपनी आजीविका के लिए यहां तक कि 20 रूपये प्रतिदिन खर्च करने में भी असमर्थ है तथा खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती जा रही है। दूसरी ओर देश में सबसे अधिक 10 अमीर व्यक्तियों की संपत्ति वर्ष 2009 में 3,55,205 करोड़ रूपये से बढ़ कर 6,05,077 करोड़ रूपये हो गई है।

इस लूट के हिस्से के तौर पर साम पित्रोदा कमेटी ने बीएसएनएल में 30 % शेयरों को बेचने और 1 लाख कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए उसने एक और कमेटी का गठन किया है। सरकार की पीएसयू विरोधी और बीएसएनएल विरोधी नीतियों के कारण बीएसएनएल को वर्ष 2009-10 के लिए 1822 करोड़ रूपये का घाटा हुआ है।

पिछली यूपीए सरकार उसे समर्थन कर रही वामपंथी पार्टियों के दबाव के कारण अर्थव्यवस्था और जनता की लूट करने की अनेक नीतियों को लागू करने में असमर्थ थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल करने और वामपंथी पार्टियों के समर्थन के बगैर सरकार बनाने के बाद वर्तमान यूपीए 2 सरकार इन धोखाधड़ी की नीतियों को लागू करने में पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिनका उद्देश्य भारतीय और बड़े पूंजीपतियों के लिए शीघ्र लाभ प्राप्त कराना है।

भारत के मजदूर वर्ग ने लूट की नीतियों के खिलाफ और बेहतरी के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु लड़ने का

निर्णय किया है। सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (इंटक, सीटू, एटक, एचएमएस, टीयूसीसी, यूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, एआईयूटीयूसी) और केंद्रीय सरकारी, राज्य सरकारी, पीएसयू कर्मचारियों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रही फेडरेशनों/यूनियनों ने इन गलत नीतियों का प्रतिरोध करते हुए 7.9.2010 को सभी क्षेत्रों में आम हड़ताल करने का आह्वान किया है।

चूंकि लूट की ये नीतियां वैश्वीकरण के नाम पर अनेक देशों में लागू की जा रही हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यूएफटीयू) ने 7 सितम्बर 2010 को सभी देशों के मजदूरों का इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है।

सभी क्षेत्रों के हरेक कर्मचारी/मजदूर के लिए यह आवश्यक है कि वह यूपीए सरकार की मजदूर विरोधी, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल में भाग ले। अब हमारे भविष्य और हमारे देश के भविष्य की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका है। अतः हम सभी बीएसएनएल कर्मचारियों से इस हड़ताल में शामिल होने और इसे शानदार रूप से सफल बनाने की अपील करते हैं।

बीएसएनएल इम्पलाईज यूनियन

--- ***जिला ब्रांच***